यूनेस्को
ऐतिहासिक नगरीय परिदृश्य पद्धति

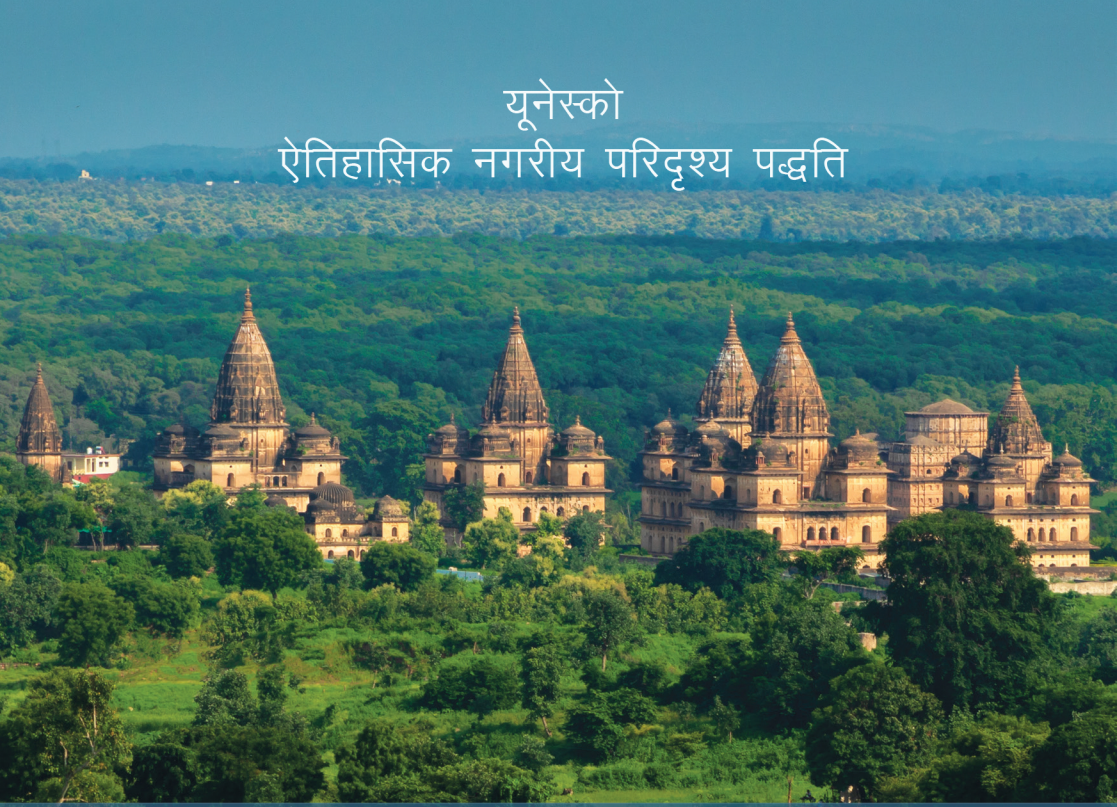

ओरछा एवं ग्वालियर
मध्य प्रदेश, भारत

प्रस्तावित कार्य :

1. शहर के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानव संसाधनों व उनसे जुडी जरूरतों से सम्बंधित आवश्यकताओं का पूर्ण मूल्यांकन ;
2. हितधारकों के परामर्शों को योजनाओ में सम्मिलित कर संरक्षण के उद्देश्यों एवं उनके क्रियान्वयन पर निर्णय लेना ;
3. सामाजिक–आर्थिक दबाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति नगरीय धरोहरों पर जोखिम का आंकलन ;
4. सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के स्वीकार्य स्तर का निर्धारण ;
5. धरोहरों के संरक्षण के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास का संतुलन ;
6. नगरीय धरोहरों के मूल्यों और उनसे जुड़े जोखिमों को समझकर नगरीय विकास के व्यापक ढाँचे में सम्मिलित करना ;
7. विकास के साथ–साथ संरक्षण के लिए नीतियों और कार्यों को प्राथमिकता देना, जिसमें धरोहरों का सुप्रबंधन शामिल हैं ;
8. उपयुक्त (सार्वजनिक–निजी) भागीदारी और स्थानीय प्रबंधन ढांचे की स्थापना ;
9. विभिन्न कारकों के बीच गतिविधियों में सहभागिता के लिए एक परियोजना विकसित करना ;

यूनेस्को
और
मध्य प्रदेश सरकार
की संयुक्त परियोजना

मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के अनुरोध पर, यूनेस्को – नई दिल्ली समूह कार्यालय द्वारा ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक नगरों के विकास एवं संरक्षण के लिए इस परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व लिया गया है। यह परियोजना न केवल नगरों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों की मूल प्रकृति के संरक्षण पर केंद्रित है, बल्कि भविष्य की योजनाओं में समाहित करते हुए जन कल्याण एवं सतत विकास पर भी ध्यान देती है।

भूमिका

आज, अधिकांश आबादी – 390 करोड़ लोग – शहरों में रहती हैं।

2050 तक, 250 करोड़ और लोग शहरों में निवास करेंगे, जिससे दुनिया में लगभग 70% शहरीकरण हो जायेगा।

भारतीय नगर, शहरीकरण के एक अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहे हैं और 2050 तक 41 करोड़ 60 लाख से अधिक निवासियों को नगरों में समाहित करने की आवश्यकता होगी (संयुक्त राष्ट्र – विश्व शहरीकरण संभावनाएं)। अक्सर इन नाटकीय बदलावों के परिणामस्वरूप नगरों में आकस्मिक एवं तीव्र गति से अनियंत्रित निजी विकास होता है, जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक पारितंत्रों एवं जनकल्याण को समग्र रूप से क्षति पहुँचता है।

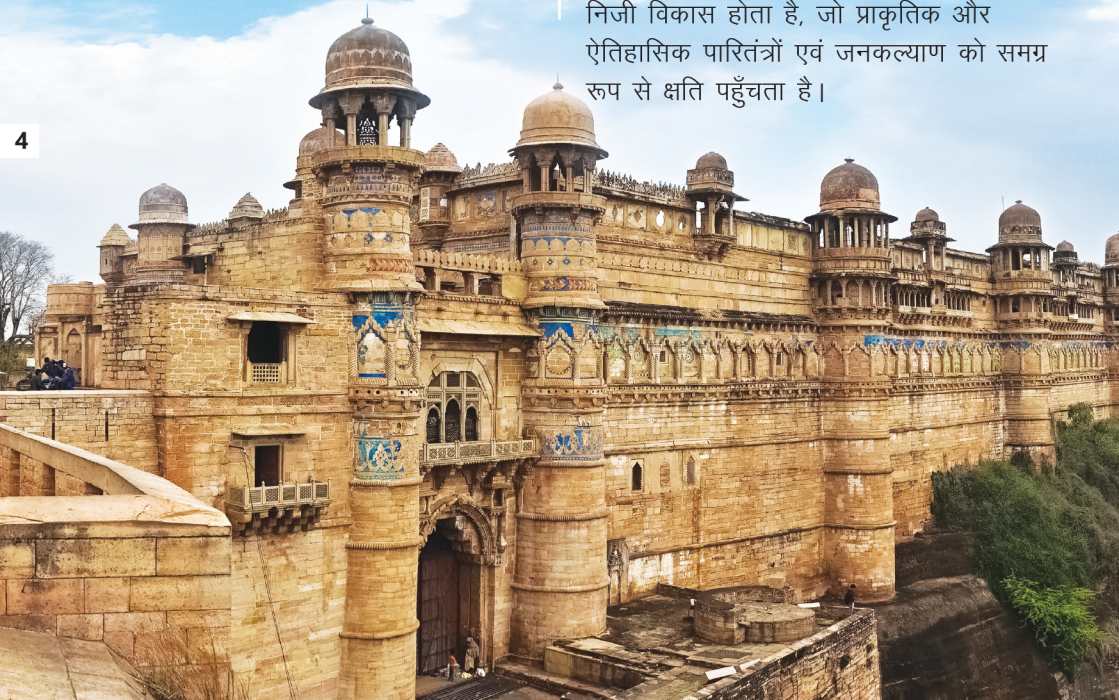

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य – 2030 (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स – 2030) में शहरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस उद्देश्य हेतु, यूनेस्को उन शहरी प्रशासनों एवं महत्वपूर्ण हितकारकों को प्रोत्साहित करता है जो सिर्फ ऊँची इमारतों और कंक्रीट जंगलों के रूप में विकास को ढूंढ़ने के बजाय, अपने ऐतिहासिक शहरों में निहित समृद्ध अतीत और सांस्कृतिक विविधता को प्रेरणा मानकर आगे बढ़ रहे हैं।

यूनेस्को द्वारा "ऐतिहासिक नगरीय परिदृश्य" के परामर्श शहरों को अपनी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों, उनकी विशिष्टताओं एवं इतिहास को संरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

इसलिए, यूनेस्को द्वारा "ऐतिहासिक नगरीय परिदृश्य" के परामर्श शहरों को अपने अतीत और धरोहरों के सामर्थ्य को समझने में मदद करती है । इस परामर्शों में समाहित बिंदु शहरों की समकालीन सामाजिक–आर्थिक विकास की जरूरतों के साथ–साथ उनकी सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा को भी महत्व देते हैं । "ऐतिहासिक नगरीय परिदृश्य" के परामर्श इस विश्वास पर आधारित है कि शहरों का जनकल्याण पर केंद्रित होकर विकास की ओर बढ़ना एक आवश्यकता है।

सतत विकास लक्ष्य 11 (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11) के अनुसार शहरी सतत विकास में संस्कृति की एक अहम् भूमिका है, विशेषतः सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की।

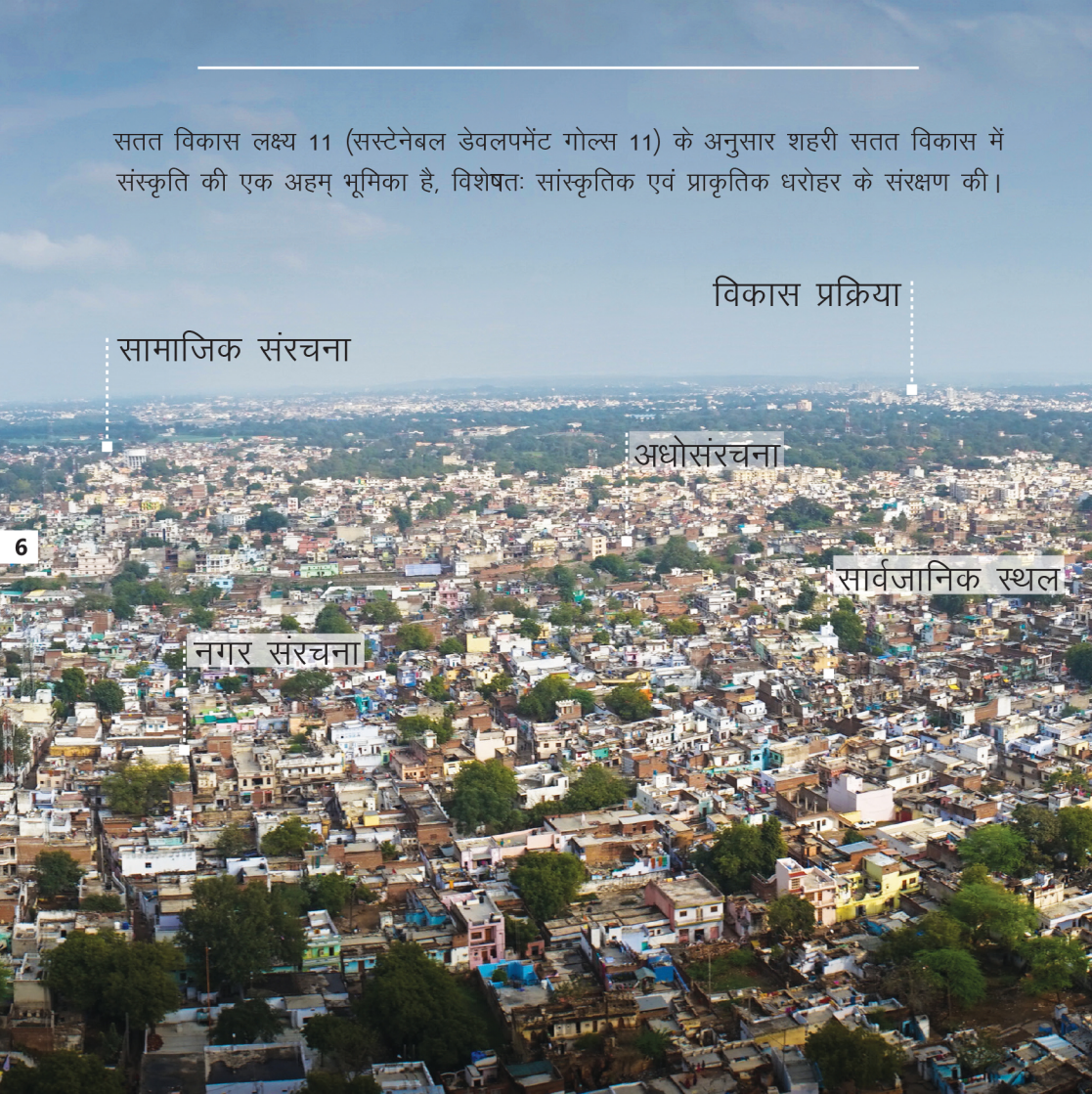

शहरी धरोहर मूल रूप से शहरों के जीवन यापन स्तर को बढ़ाने में योगदान देती है एवं आज कल के बदलते वैश्विक परिवेश में, ऐतिहासिक शहरों के आर्थिक विकास और सामाजिक एकता को प्रोत्साहन देती है।

सौजन्य से

मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड

The heart of
Incredible !ndia

सहयोग से

धरातल

संपर्क : **newdelhi@unesco.org**

छायांकन © 2021 धरातल एवं मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड